अमृत वाणी

स्वतंत्र वही से सकता है जो अपना काम अपने आप कर लेता है।

-विनोबा,

हादसों का दिन

बस्तर के लिए 9 अगस्त का दिन हादसों से भरा रहा और विडंबना यह है कि सारे हादसे मानवीय भूल, लापरवाही और गलत सोच के नतीजे है। दुख इस बात का है कि एक तो करता कोई है, कीमत किसी और को चुकाना पड़ता है और दूसरा यह कि कतिपय लोग जबरन हादसों को न्यौता देकर अपनी तथा दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं।

सर्वाधिक दर्दनाक हादसा जो गुरुवार को संभाग मुख्यालय के रेल्वे कालोनी में हुआ उस पर गौर करें। आए दिन देश में चारों ओर बोरवेल के खुले गड्ढों में बच्चों के गिरने से भयावह हादसों के मद्देनजर खुले गड्ढे नहीं छोड़ने के बारे में सचेत किया जाता है। बावजूद लगता है कुछ लोगों ने ऐसी गल्तियां करने की ठान सी ली है। निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार ने गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जबकि बारिश के इस मौसम में इन गड्ढों में पानी भरा रहना और भी खतरनाक होता है। जिस बात का डर रहता है वही हुआ, दो बच्चों की उस पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। अब इसके लिए संबंधित जिम्मेदारों को चाहे कितनी भी सजा क्यों न मिले क्या इस नुकसान की कभी पूर्ति हो सकती है।

उसी तरह अगर यात्री बसों में आगजनी और यात्री ट्रेन को डीरेल किए जाने की घटनाओं को देखें तो एक ही सवाल खड़ा होता है कि मासूम यात्रियों का क्या दोष है। उन्हें बार-बार ऐसी परेशानियों से जूझना क्यों पड़ता है। ट्रेन डी रेल होने से भले ही ईश्वर की महान कृपा वश यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आई हो लेकिन बस में किसी अज्ञात व्यक्ति की जली हुई लाश मिलना ऐसे हादसों की भयावहता और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। सुरक्षित यात्रियों पर ऐसी घटनाओं का मानसिक प्रभाव भी कम नहीं होता।

दिन का तीसरा हादसा तो जान बूझकर गले लगाने जैसा था। बारिश के दिनों में बार-बार ऐसे पुल पर से यातायात नहीं करने की चेतावनी दी जाती है जिनके ऊपर से नदी-नाले में आई बाढ़ का पानी बह रहा हो क्योंकि पानी अगर कम भी हो तो भी उसके धार की तेजी का अनुमान किनारे से लगाना संभव नहीं होता। वहीं हुआ उस वाहन के चालक के साथ जिसने पोरेडाबहार नाले के पुल के ऊपर से पानी बहता देखकर भी आनन फानन में उस पर वाहन चढ़ा दिया। नतीजा यह कि पलक झपकते पानी के तेज बहाव में वाहन बह गया। वाहन में सवार एक युवक तो जैसे तैसे बच निकला पर चालक का कोई पता नहीं।

समझ में नहीं आता कि लोग बार-बार एक जैसी लापरवाहियां, भूल और गलत कदम क्यों ठठाते है। ऐसा करके वे स्वयं के साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं जबकि जरा सी सावधानी, सतर्कता और सकारात्मक सोच ऐसे अनेक हादसों को आसानी से टाल सकता है।

राजकाज

कब तक खेलेंगे टोपी-टोपी

पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर टोपी धारण करने से मना किया था तो हंगामा मच गया था और उन्हें मुस्लिम विरोधी तक बता दिया गया। ऐसे में नगालैंड की पारंपरिक टोपी को विचित्र बताकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तो मानों खुद ही आ बैल मुझे मार वाली उक्ति को सार्थक कर दिया है। दरअसल थरूर की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नेफ्यिू रियो ने गंभीर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। दरअसल रियो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नगाओं का समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृति है। हमें अपने इतिहास और परंपराओं पर गर्व है। नगा टोपी के बारे में सभी जानते हैं। यह विचित्र नहीं है। परस्पर सम्मान भारत को महान देश बनाता है। भावनाओं को आहत करने वाले बयान के लिए वह माफी मांगे और इसे वापस ले। अब चूंकि रियो नगालैंड में पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रमुख हैं और भाजपा भी उनके गठबंधन में शामिल है अतरू समझा जा सकता है कि यह एक राजनीतिक विवाद ही है, जिसे भुनाने की भरसक कोशिश की जाएगी। बहरहाल जानकार कह रहे हैं कि आखिर ये नेता टोपी-टोपी खेलना कब बंद करेंगे, क्योंकि और भी गम हैं जमाने में टोपी के सिवाए।

शेल्टर होम! यूं भी लें सबक

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में लड़कियों से रेप के मामले को उजागर हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी इसी तरह का मामला उजागर हो गया। यही वजह है कि दिल्ली महिला आयोग ने इन घटनाओं से सबक लेते हुए राजधानी दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के सभी शेल्टर होम्स के सोशल ऑडिट का आदेश दे दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि सभी शेल्टर होम्स की विस्तृत और गहराई से जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार और महिला आयोग के इस कदम का स्वागत किया गया है और कहा जा रहा है कि काश अन्य राज्य भी इसी तरह के आदेश देकर पूर्व में घटित घटनाओं से सबक लें तो बेहतर होगा।

उचित नहीं एनआरसी पर स्वार्थपूर्ण राजनीति

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की 30 जुलाई को जारी दूसरी सूची के बाद इसमें करीब चालीस लाख लोगों के नाम न होने को लेकर इन दिनों देश में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा छिछले स्तर पर राजनीति की जा रही है। एनआरसी की वर्तमान सूची के अनुसार 28938677 लोगों की नागरिकता की पुष्टि हुई है जबकि 4052703 लोग एनआरसी से बाहर हैं। एक ओर जहां स्वार्थपूर्ण राजनीति के चलते कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसी बहाने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वहीं भाजपा इस मामले में फूंक-फूंककर कदम रख रही है क्योंकि इसके राजनीतिक प्रभाव के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश के आपसी रिश्तों पर भी इसकी आंच आ सकती है। संभवतः यही कारण है कि सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों से बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे और पुष्ट प्रमाण न मिलने पर ऐसे लोग असम के नागरिक नहीं माने जाएंगे लेकिन सरकार उनके खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करेगी और न ही उन्हें विदेशी घोषित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि असम में एनआरसी का मसौदा उच्चतम न्यायालय की निगरानी में तैयार हो रहा है। अदालत ने 17 दिसम्बर 2014 को इसे अपडेट तथा प्रकाशित करने की समय सीमा तय की थी, जिसकी अंतिम सूची एनआरसी से बाहर रह गए 40 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों के निपटान के बाद इस साल के अंत तक आने की संभावना है। बता दें कि एनआरसी एक ऐसी सूची है जिसमें असम में रहने वाले उन लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनके पास 24 मार्च 1971 तक अपने परिवार के असम में होने के प्रमाण हैं, ऐसे लोगों को ही असम का नागरिक माना गया है। 1951 में कांग्रेस सरकार ने नागरिकों का डाटा रखने के लिए एनआरसी बनाया था। वैसे देश की आजादी के इतने सालों बाद तक असम ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां नागरिक रजिस्टर की व्यवस्था है। 1979 में असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफहिंसक आन्दोलन शुरू हो गए थे और कई वर्षों के संघर्ष के बाद 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच असम समझौते पर सहमति बनी थी, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण अद्यतन किए जाने का उल्लेख था। असम समझौते के तहत 24 मार्च 1971 तक भारत आए लोगों को ही यहां का नागरिक माना गया, 1951 से 1961 के बीच प्रवेश में आए लोगों को पूर्ण नागरिकता तथा वोट देने का अधिकार मिला जबकि 1961 से 1971 के बीच आए लोगों को नागरिकता के साथ अन्य अधिकार तो मिले किन्तु वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। 2005 में केन्द्र और असम सरकार के बीच भी समझौता हुआ, जिसके बाद सरकार ने असम के कुछ जिलों में एनआरसी को अपडेट करने का कार्य शुरू किया किन्तु प्रदेश में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। अंततः 2009 में एक एनजीओ असम पब्लिक वर्क ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद अब कोर्ट में निगरानी में ही एनआरसी अपडेट का कार्य हो रहा है।

एनआरसी में 40 लाख लोगों के नाम न होने के बाद बहुत से लोगों के मन में अब यह प्रश्न उमड़ रहा है कि आखिर असम में एनआरसी अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ीघ् दरअसल असम में पिछले कुछ दशकों में मुस्लिमों और मतदाताओं की संख्या जिस प्रकार अप्रत्याशित रूप से बढ़ी तेजी से बढ़ी, उसे लेकर लंबे समय से विवाद खड़ा होता रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। 1971 से 1991 के बीच ही प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 89 फीसदी और 1991 से 2011 के बीच 53 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1951 से लेकर अब तक असम की जनसंख्या में 4 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1951 में प्रदेश की आबादी 80ण्3 लाख थी, जो अब करीब 3ण्30 करोड़ हो चुकी है और आबादी बढ़ने की यह रफ्तार 1971 के बाद से ही काफी तेज है। 1971 तक प्रदेश में कुल 6268273 मतदाता थे किन्तु 1971 से 2011 के बीच करीब सवा करोड़ मतदाता और जुड़ गए और 2011 तक मतदाताओं की संख्या 18188269 हो गई। दुबरी, मोरीगांव, गोलपाड़ा, दरांग, नोगोंग, करीमगंज, हैलाकंडी, बरपेटा, बोगलगांव, कछार, धेमाजी, कामरूप, कबीं अंगलांग, लखीमपुर इत्यादि राज्य के 14 जिले तो ऐसे हैं, जहां जनसंख्या में वृद्धि का औसत राज्य की औसत वृद्धि दर से काफी ज्यादा है। प्रदेश में मतदाताओं तथा आबादी के तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण अवैध रूप से भारत आए बांग्लादेशी नागरिक माने जा रहे हैं। राज्य के दर्जनभर जिलों में मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से भी अधिक है। 126 विधानसभा सीटों में से 40 पर बांग्ला भाषी मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है और दो दर्जन से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मंगलदोई, नोगोंग, सिलचर इत्यादि 14 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम तथा अप्रवासी मतदाताओं का वर्चस्व है।

कुछ माह पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत ने एक सेमिनार में असम में बांग्लादेशी घुसपैठ और एक राजनीतिक पार्टी के चंद वर्षों में तेजी से हुए उभार को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर बवाल मच गया था। असम के कुछ जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि की खबरों का हवाला देते हुए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोटिक फ्रंट एआईयूडीएफ की चर्चा करते हुए सेना प्रमुख ने कहा था कि राज्य में इस पार्टी का उभार देश में भाजपा के विकास से भी अधिक तेज गति से हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 1984 में भाजपा को सिर्फदो सीटें मिली थी और उसे उभरने में वर्षों लग गए लेकिन असम में एआईयूडीएफएक ऐसी पार्टी है, जो बहुत ही कम समय में उभर गई और उसकी ताकत बढ़ने की रफ्तार भाजपा से भी ज्यादा है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है, ऐसे में सेना प्रमुख की चिंता वाजिब थी।

वर्ष 2005 में असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी एआईयूडीएफ का गठन किया था, जिसकी प्राथमिकता ही राज्य में मुस्लिमों की आवाज बनना रहा है। महज 12 वर्षों में यह पार्टी असम की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई, जिसने 2016 में 126 सदस्यीय विधानसभा में 13 विधानसभा सीटें जीतने के अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटें जीतने में सफलता पाई लेकिन यह तस्वीर का सिर्फएक पहलू है। तस्वीर का दूसरा बदरंग पहलू यह है कि बदरुद्दीन अजमल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण और पनाह देने के तथा असम में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं और उन्हीं की बदौलत पार्टी ने असम में इतने कम समय में इतनी ताकत हासिल कर ली। बदरुद्दीन अजल असम की राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार है तो सिर्फदेश घुसपैठियों की ही बदौलत। आज असम में आबादी के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, वहां के 9 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व है, जिनके आधार कार्ड व मतदाता पहचानपत्र बनाकर उन्हें बाकायदा वहां का नागरिक बनाने की कोशिशें की गई हैं। बहुत ही कम समय में असम में मुस्लिम आबादी 31 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। क्या ऐसे में यह जानने की आवश्यकता महसूस नहीं की जानी चाहिए कि यह सब किस षड्यंत्र के जरिये संभव हो रहा है।

योगेश कुमार गोयल
(दे लेखक के अपने विचार है)

खुशबु आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से

नितिन गडकरी कहते हैं कि आरक्षण मिलने पर क्या नौकरी मिल जाएगी वहां मुख्य मंत्री मनपसंद सरकार श्री शिवराज सिंह कहते हैं की यह सच है की छत्तरपुर जिले में पोलियो की दवा पिलाने दस किलोमीटर तक सड़क न होने से नदी तैरकर भी जाना पड़ता है ! ये स्वयं देश ध्यदेश के भाग्य विधाता कह रहे हैं। जनता तो सब जानती हैं। मध्य प्रदेश में शासन तो लोकप्रिय नेतृत्व का है जिन्होंने पूरे प्रदेश को मनपसंद सरकार का दर्जा दिलाया। पूरे प्रदेश में विकास ध्गंगा की गंगा बह रही हैं। सच में बिजली पानी सड़क शिक्षाए स्वास्थ्यएअपराधए बलात्कारए भवन निर्माणों मेंए अफसरोंए नेताओं की आर्थिक उन्नति बहुत हुई और कांडो ध्घोटालों में कोई कमी नहीं। चाहे डंपर काण्डएरेत खनन काण्डए व्यापम काण्ड तो मध्य प्रदेश का पर्यायवाची नाम हैं। किसी से अब कहने की जरुरत नहीं हैं की हम मध्य प्रदेश के निवासी हैंए बस कह दो व्यापम काण्ड याने मनपसंद प्रान्तए और तो और पर्यावरण के नाम पर नर्मदा के किनारे लगाए गए वृक्षारोपण भी एक घोटाले का नाम हैं। जितनी प्रशंसा की जावे वह कम हैं और उसके बाद भी मिस से चाहत हैं मुखिया बनने की। भैय्या अब दूसरों को भी मौका दो विकास करने का। खुद काए पार्टी का और प्रदेश का।

वर्ष 2014 में चुनावी भाषणों और लच्छेदार बातों से एक अच्छे नेता और राजनैतिक पढ़े लिखे होने का अवसर लेने पर प्रधान सेवक जो अपने आपको चौकीदार कहते हैं को भारत की गद्दी मिली और वे प्रधान सेवक बने और बनते ही संसद की सीढ़ी के पाँव पड़कर और उसे रौंदकर आगे बढे। वास्तव में चुनाव की रैलियों चायवाला और गरीब व्यक्ति का जो रूप दिखाया जिससे भारत के गरीबों का दिल भर आया और उन्हें विश्वप्रधी दिलाई। चूँकि परिवर्तन का दौर था। विजय होकर 27 मई 2014 को गद्दीनशीन हुए और भारी बहुमत से प्रगट हुए भारत के नए युग की शुरुआत करने जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से देश को थी।

आपके चुनावी घोषणा पत्र में 50 चुनावी वादे किये गए थे जिनमे प्रमुखता से अयोध्या में राम मंदिर निर्माणए धारा 370 को लागु करनाए हिंदुत्व एजेंडा और देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना। इसके अलावा आपने गद्दी पर बैठते हुए अपने अनुभवों के आधार पर प्रधान मंत्री जन धन योजना जिसमे शून्य जमा पर खाता खोलना और नोवेम्बर 2017 तक307 मिलियन खाते खोले गए जिसमे खाली खातों से बैंक 2434करोड से मालामाल हुए!

वर्ष 2015 में सुकन्या समृद्धि खाता योजना के द्वारा लाभ दिया गया। हुए 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर गरीबों को दिए गए। कितने पहुंचे जमीनी स्तर पर यह संदेहजनक है। सितम्बर 2104 में आपके द्वारा मेक इन इंडिया की घोषणा की हुए 25 क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाई पर वास्तविक गंगा आज भी मरणासन्न हो रही हैं। आपके द्वारा पहले ?फ्डी आई का विरोध किया गया था पर किस कारण आपको देश का लाभ दिखा और उसे लागु किया। आपके द्वारा जापान और इंडिया के अंतरगत एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। जिससे मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रैन चलाई जाएँगी। इस राशि शून्य ब्याज पर मिलेंगी और निर्माण कार्य जापान करेगा और उसकी ऊपयोगिता का प्रतिशत कितना होगा यह वो जाने। पर इससे बड़ा छलावा क्या होगा की हम झूठे विकास की ओर मृगतृष्णा कर रहे हैं। अभी इंडिया की रेल की अधोसंरचना संतोषजनक नहीं हैए पहले उस पर विचार करना चाहिए। शायद प्रधान सेवक सेवा निवृत्ति के बाद उसमे यात्रा करेंगे घ्कारण भ्रष्टचार रहित इंडिया के वे एक मात्र प्रधान सेवक होंगे। उनका मन देहली में तो लगेगा नहीं। जी एस टी के द्वारा व्यापार धरातल पर चला गया हैं। आंकड़ों का छद्मजाल बहुत भ्रमित करता हैं

इस परम्परा को देखते हुए कई राज्यों ने इसका पालन किया जैसे हरियाणा ने हैप्पिंग हरियाणाएमहाराष्ट्र ने मैग्नेटिक महाराष्ट्रा। और हमारे प्रिय मनपसंद प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराजसिंह ने तो दोनों हाथों से प्रदेश का कोष खोल कर जन्म से लेकर अंत समय की इतनी योजनाएं घोषित की हैंकी आगामी आने वाली सरकार को कर्ज़ का इतना बोझ ढोना होगा जो अकल्पनीय हैंहां इससे उनका और उनके कार्यो को बहुत लाभ मिला। इसके बाद भ्रष्टाचार रोकने केंसलेस इकोनॉमी शुरू की डिजिटल इंडियाए डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की। राफेल कांड और राष्ट्रीय राजमार्गों में होने वाली अनियमितता आगे चलकर कांड होगा। हमारे देश के लिए गौरव की बात हैं की प्रधान सेवक फ्रोब्स 2018 की सूची में 9 वे नंबर पर हैं टाइम्स ग्रुप के द्वारा किये गए सर्वेक्षण में प्रधान सेवक को 72: और राहुल गाँधी को 12: पसंदगी रही ! प्रधान सेवक द्वारा एक क्रन्तिकारी कदम उठाया गया नोट बंदी जिसको 22: ने असफल माना 28: के द्वारा नौकरी देने में असफल हैंए 15: का कहना है की कश्मीर मामले में फ्रैल और 55: कहना हैं की पाकिस्तान के मामलों में कुछ सुधार नहीं हुआ। हमारा देश वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता में बहुत चिंतनीय स्थिति में हैं विश्व प्रेस स्वतंत्र सूची 2018 में 180 देशों में 138 नंबर हैं जबकि पाकिस्तान 139 नंबर हैंए राणा अयूब की पुस्तक गुजरात फ्राइल्स 2016 में 2002 के दंगों में राजनेताओं और नौकरशाह की अहम भूमिका रही जिस कारण उन्हें जान से मारने और बलात्कार जैसे हथकंडों के तहत धमकियाँ मिली जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना पड़ा था और सुरक्षा प्रदान करने का निवेदन किया गया। वर्तमान में ज्वलंत प्रकरण ए बी पी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर और पुण्य प्रसून बाजपेयी के द्वारा प्रधान सेवक कोग्रामीण योजना का पर्दाफ्राश किएए सच को झूठ साबित किया उससे अप्रसन्नता जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं और प्रधान सेवक कार्यालय की शह पर उन्हें स्तीफ देना पड़ा। यह एक प्रकार से सूचना तंत्र पर पूरा नियंत्रण कसा जा चुका हैं।

इसी प्रकार सरकार का और प्रधान सेवक का धरा 377 पर चुप रहना यह दर्शाता हैं की सरकार ने इसका समर्थन किया और इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा कर रही हैं। जबकि एक सांसद ने इसे शृंखि सुरक्षा का खतरा बताया। वर्ष 2016 में प्रधान सेवक ने ऑलैंड के गे क्लब की गोलीबारी की निंदा की और दुःख व्यक्त किया था।

हम जानते हैं प्रधान सेवक बहुत ईमानदार हैं क्योंकि वे अलीबाबा हैं पर उन्होंने चालीस चोरों को खुली छूट दे रखी हैं जिससे उनका भवन बनाए उनको चुनाव लड़ना हैं। देखो जमीनी हकीकत तो सब जानते हैं। प्रधान सेवक की विदेश यात्राओं में जो मजमा लगता था वह सब प्रायोजित रहता हैं। देश में भी उनकी आम सभा बहुत खर्चीली होती हैं और जो प्रधान सेवक हैं वे जरूर गरीब हैं पर उनकर ठाठ गरीब अमीर रहते हैं। उनके मजमाए जुमलों से अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ताए अब तो जनता ने टी वी देखना बंद कर दिया हैंए समाचार पत्र में भी कोई रूचि नहीं हैंए सोशल मीडिया भी नकली और हास्यपद जुमलों से भरे पड़े हैं जो नापसंद किये जा रहे हैं।

टी वी में जो नूरा कुश्ती होती हैं और जो ज्ञान संस्कृति का परिचायक हैं कोई किसी की बात न सुनना चाहता हैं और और कोई सार्थक बहस नहीं। वे ही घिसी पिटी सूरतें जो सब विषयों के जानकार लगते हैं पर होते नहीं। समय खराब करना। हाँ मोदी विकास की गंगा बहना चाहिए और मोदी प्रशंसा बस अन्यथा इस्तीफ़ा मंजूर होना निश्चित। इससे यह जाहिर हो गया हैं की जो सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन सकती वह आँख होते हुए अंधी और कान होते हुए बहरी जैसे होते हुए गूंगी हैंए इससे भविष्य अंधकारमय रहेगा और इसका दुष्परिणाम भोगना होगा जनता और नेताओं को वर्ष 2019 का चुनाव या आगामी चुनाव में जनता का फैसला ही करेगी मोदी हमारी आशा हैं और कुछ का कहना हैं शब्दजाल और मदारी से देश को बचाना हैं पर जितनी अपेक्षा थी उतने कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब जो कहना रहेगा वह राग अलापना रहेगा।

अरविन्द जैन
(दे लेखक के अपने विचार है)

जिन्ना का जिन्न दलाईलामा में समाया

तिब्बत के धर्मगुरू दलाईलामा पिछले साठ सालों से तिब्बत छोड़कर भारत में डेरा डाले हुए है, उन्हें मार्च, 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने उनके सैकड़ों शिष्यों के साथ भारत में शरण दी थी, दलाईलामा को शरण देने के कारण आज तक चीन भारत से नाराज है, किंतु पिछले साठ साल से भारत का नमक खाने वाले दलाईलामा में भारत के नमक का असर दिखाई देने लगा है और वे उसी शख्स को शालीन शब्दों में गालियाँ दे रहे है जिसने उन्हें भारत में शरण दी और चीन से स्थाई दुश्मनी मोल ली, जी मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का ही यहां जिक्र कर रहा हूँ, जिनके बारे में हाल ही में 83 वर्षीय दलाईलामा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आत्म केन्द्रित शख्स थे वे सिर्फअपने बारे में ही सोचते थे वे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की वह सलाह ठुकरा दी जिसमें गाँधी जी नेहरू की जगह तत्कालीन मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद सौंपना चाहते थे। दलाईलामा ने इससे भी आगे बढ़कर यह भी कहा कि. अगर जिन्ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का विभाजन नहीं होता और पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। अब तिब्बती धार्मिक गुरू की यह दलील भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को कैसी लगेगी यह तो नहीं कहा जा सकता संभव है उन्हें नेहरू के प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने की दलील पसंद आए किंतु लाला की दलील का दूसरा भाग तो प्रधानमंत्री क्या भारत में किसी को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि वे उस मुस्लिम नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे है जिसकी महज एक तस्वीर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे देश में कुछ दिन पहले कोहराम मच चुका है और अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना की मजार पर जाने के कारण भाजपा के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवानी विवादों के घेरे में आ चुके है।

यद्यपि यहाँ यह भी स्मरणीय है कि तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा के ही ऐसे ही शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी लोह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में पहले कई बार दोहरा चुके है, नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा था. महात्मा गाँधी नेहरू की जगह सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, किंतु नेहरू ने गाँधी की बात नहीं मानी और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए‍ए यदि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बना दिए गए होते तो आज देश की तस्वीर कुछ अलग ही होती न पाकिस्तान होता और न जम्मू.कश्मीर विवाद।

इस तरह यदि दलाईलामा और नरेन्द्र भाई के बयानों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फप्रथम प्रधानमंत्री के प्रस्तावित नामों को छोड़ दोनों बयान लगभग एक जैसे ही है, एक पाक के कायदा.ए.आजम मरहूम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का जिक्र कर रहा है तो दूसरा लोह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अर्थात् दोनों का उद्देश्य एक ही समान पंण् नेहरू को कोसना रहा।

इन दिनों हमारे देश में हमारा इतिहास बदलने की चर्चाएँ चल रही है, देश की नई पीढ़ी को हमारे देश के इतिहास की वंचित काली परछाईयाँ हटा कर रोशनीदार इतिहास पढ़ाने की बात की जा रही है तो क्या अब तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा भी तो इस इतिहास बदलू गिरोह में शामिल तो नहीं हो रहे हैघ् या उनकी अपनी अपनी उनकीनिजी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने जिन्ना की वकालत करने के दौरान ही चीन को कोसते हुए युरोपिय संघीय संगठन की तारीफभी की और गोवा प्रबंधन संस्थान के छात्रों को यह भी बताया कि किंतु घातक परिस्थितियों में रातों.रात उन्हें तिब्बत से भागकर भारत आना पड़ाघ् दलाईलामा ने तो यहाँ तक कहा कि यदि वे 17 मई, 1959 को भारत में आकर शरण नहीं लेते तो वे आज जिन्दा ही नहीं होते। यद्यपि दलाईलामा के इस भारत वर्षीय इतिहास के गढ़े गढ़ें उखाड़ने के प्रयास से सम्बंधित बयान पर कोई विशेष राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त नहीं हुई है, किसी ने एक शरणागत विदेशी धर्मगुरू के ऐसे विवादित बयान पर टिप्पणी भी नहीं की, किंतु इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही।

ओमप्रकाश मेहता
(दे लेखक के अपने विचार है)